भारत सरकार
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय
पशुपालन और डेयरी विभाग
लोकसभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 2803
दिनांक 18 मार्च, 2025 के लिए प्रश्न

दूध का उत्पादन

2803. **श्री विष्णु दयाल राम:**

क्या **मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय को इस बात की जानकारी है कि राज्यों में जैसे असम में 1.49 किलोग्राम से लेकर पंजाब में 13.31 किलोग्राम तक प्रति गाय दूध उत्पादन में व्यापक अंतर है;

(ख) इस असमानता को दूर करने और असम, छत्तीसगढ़ और झारखंड जैसे कम प्रदर्शन करने वाले राज्यों में दूध उत्पादन में सुधार लाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या इन क्षेत्रीय अंतरों को दूर करने के लिए लक्षित प्रजनन, आहार और स्वास्थ्य देखभाल पहलों को लागू किया जा रहा है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री
(प्रो. एस. पी. सिंह बघेल)

(क) से (घ) जी हां। भारत सरकार असम, छत्तीसगढ़ और झारखंड सहित कम निष्पादन करने वाले राज्यों में लक्षित प्रजनन, आहार और स्वास्थ्य देखभाल के माध्यम से बोवाईन पशुओं के दूध उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित योजनाएं/कार्यक्रम लागू कर रही है और निम्नलिखित कदम उठाए हैं:

1. राष्ट्रीय गोकुल मिशन: इस योजना के अंतर्गत की गई पहलें इस प्रकार हैं:

(i) 50% से कम कृत्रिम गर्भाधान कवरेज वाले 605 जिलों में कृत्रिम गर्भाधान (एआई) कवरेज बढ़ाने के लिए राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम (एनएआईपी) शुरू किया गया है, जिसमें असम के 35 जिले, छत्तीसगढ़ के 33 जिले, झारखंड के 24 जिले शामिल हैं। कार्यक्रम को मिशन मोड में लागू किया गया है और किसानों के द्वार पर गुणवत्तापूर्ण एआई सेवाएं निःशुल्क प्रदान की गई हैं और अब तक 8.39 करोड़ पशुओं को कवर किया गया है, 12.34 करोड़ कृत्रिम गर्भाधान किए गए हैं और 5.21 करोड़ किसान लाभान्वित हुए हैं। असम, छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य में कार्यक्रम के तहत की गई प्रगति निम्नलिखित तालिका में दी गई है :

क्र.सं.	राज्य का नाम	गर्भाधान किए गए पशुओं की संख्या	किए गए कुल कृत्रिम गर्भाधान	लाभान्वित किसान
1	असम	1559269	1950297	1340396
2	छत्तीसगढ	1761798	2279156	1075532
3	झारखंड	2446101	3129541	1702127

कृत्रिम गर्भाधान में सेक्स सॉर्टेड सीमन का उपयोग करते हुए त्वरित नस्ल सुधार कार्यक्रम शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य 90% सटीकता के साथ बछियों का उत्पादन करना है, जिससे असम, छत्तीसगढ़ और झारखंड सहित पूरे देश में दुधारू गोपशुओं की आबादी, नस्ल सुधार और किसानों की आय में वृद्धि हो सके।

बोवाइन आबादी में तीव्र आनुवंशिक वृद्धि हासिल करने के लिए बोवाइन आईवीएफ तकनीक शुरू की गई है। आईवीएफ प्रयोगशालाओं की स्थापना के लिए असम और छत्तीसगढ़ को निधियां जारी की गई हैं।

किसानों के द्वार पर गुणवत्तापूर्ण कृत्रिम गर्भाधान सेवाएँ प्रदान करने के लिए सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों - ग्रामीण भारत में बहुउद्देश्यीय कृत्रिम गर्भाधान तकनीशियन (मैत्री) को प्रशिक्षित और सुसज्जित किया गया है। पिछले 3 वर्षों के दौरान 38,736 मैत्री को प्रशिक्षित और सुसज्जित किया गया है। असम राज्य में 1012, झारखंड में 1068 और छत्तीसगढ़ में 425 मैत्री को शामिल किया गया है।

(ii) संतति परीक्षण और नस्ल चयन कार्यक्रम के तहत उत्पादित उच्च आनुवंशिक गुणता वाले (एचजीएम) सांडों को सहित वीर्य स्टेशनों को उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें बारपेटा असम और दुर्ग, छत्तीसगढ़ में स्थित वीर्य स्टेशन भी शामिल हैं। बोवाइन आबादी से उच्च आनुवंशिक लाभ प्राप्त करने के लिए राज्यों को राष्ट्रव्यापी कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम में एचजीएम सांडों के वीर्य की खुराक का उपयोग करने की अनुमति है।

(iii) गोपशुओं और भैंसों के आनुवंशिक सुधार में तेजी लाने के लिए, सरकार ने एकीकृत जीनोमिक चिप्स विकसित की हैं - देशी गोपशुओं के लिए गौ चिप और भैंसों के लिए महिष चिप - जो विशेष रूप से देश में उच्च आनुवंशिक गुणता वाले बोवाइन पशुओं के जीनोमिक चयन को शुरू करने के लिए डिज़ाइन की गई हैं।

2. भारत सरकार चारा किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) की स्थापना को समर्थन दे रही है, जिसका उद्देश्य चारा उत्पादों - साइलेज, भूसा (हे), सूखा चारा ब्लॉक, कुल मिश्रित राशन (टीएमआर), रोपण सामग्री, चारा बीज आदि के उत्पादन और बिक्री की संगठित प्रणाली तैयार करना और देश में चारे की मांग और आपूर्ति के बीच के अंतर को कम करना है। अब तक झारखंड में स्थापित 2 चारा एफपीओ सहित 100 चारा एफपीओ पंजीकृत किए गए हैं।

3. सरकार असम, छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्यों सहित पूरे देश में राष्ट्रीय पशुधन मिशन योजना के तहत पशु चारा और आहार विकास संबंधी उप-मिशन लागू कर रही है। शामिल किए गए निम्नलिखित कार्यकलापों का विवरण इस प्रकार है: (i) गुणवत्तापूर्ण चारा बीज उत्पादन के लिए सहायता: केंद्र और राज्य सरकार के संस्थानों द्वारा सभी श्रेणियों के चारा बीजों के उत्पादन के लिए 100% प्रोत्साहन; (ii) पशु आहार एवं चारे में उद्यमिता कार्यकलाप: घास/साइलेज/कुल मिश्रित राशन (टीएमआर)/चारा ब्लॉक जैसे मूल्यवर्धन के लिए व्यक्तियों, एसएचजी, एफसीओ जेएलजी, एफपीओ, डेयरी सहकारी समितियां, सेक्शन 8 कंपनियों को प्रोत्साहित किया जाता है; और 50 लाख रुपये तक की एकमुश्त 50% पूंजी सब्सिडी प्रदान की जाती है। (iii) चारा बीज प्रसंस्करण अवसरंचना (प्रसंस्करण और ग्रेडिंग इकाई / चारा बीज भंडारण गोदाम) के लिए उद्यमियों की स्थापना: कंपनियों, स्टार्ट-अप / एसएचजी / एफपीओ / एफसीओ / जेएलजी / सहकारी समितियों, धारा 8 कंपनियों और अन्य विश्वसनीय संगठनों को चारा बीज प्रसंस्करण अवसरंचना की स्थापना के लिए 50 लाख रुपये तक की एकमुश्त 50% पूंजीगत सब्सिडी प्रदान की जाती है और (iv) गैर-वन बंजर भूमि / रेंजलैंड / गैर-कृषि योग्य भूमि से चारा उत्पादन" और "वन भूमि से चारा उत्पादन"।

4. पशुधन स्वास्थ्य और रोग नियंत्रण कार्यक्रम : यह योजना खुरपका और मुंहपका रोग, ब्रुसेलोसिस जैसे पशु रोगों के नियंत्रण के लिए सहायता प्रदान करने और असम , छत्तीसगढ़ और झारखंड सहित अन्य राज्यों को डेयरी पशुओं सहित पशुधन के अन्य संक्रामक रोगों के नियंत्रण के लिए सहायता प्रदान करने के लिए लागू की गई है। टीकाकरण कार्यक्रम के तहत: (i) एफएमडी के लिए 109.55 करोड़ से अधिक टीकाकरण किए गए हैं और (ii) ब्रुसेलोसिस नियंत्रण कार्यक्रम के तहत लगभग 4.57 करोड़ बछड़ों को ब्रुसेलोसिस के लिए टीका लगाया गया है। असम, छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्य में टीकाकरण की प्रगति निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

राज्य	एफएमडी (आज तक टीकाकरण के आंकड़े लाख में)	ब्रुसेला (अब तक टीकाकरण के आंकड़े लाख में)
असम	187.74	11.08
छत्तीसगढ	341.48	7.54
झारखंड	296.97	19.06

भारत सरकार किसानों के द्वार पर रोग निदान, उपचार, टीकाकरण, मामूली शल्य चिकित्सा हस्तक्षेप, दृश्य-श्रव्य सहायता और विस्तार सेवाओं सहित पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए मोबाइल पशु चिकित्सा इकाइयों (एमवीयू) की स्थापना का समर्थन कर रही है और अब तक 28 राज्यों में 4016 एमवीयू चालू की गई हैं और 65 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं।

******